नगा नेता अब आरपारकी लड़ाईके मूडमें

16/06/2010

16-6-10

मणिपुर, नगालैण्ड, असम और अरुणाचल प्रदेशके नगाबहुल इलाकोंको मिलाकर 'स्वतन्त्र सम्प्रभु नगालिम राष्ट्र' (राज्य नहीं) की मांग केन्द्रसे मनवानेके लिए एनएससीएन (मुइवा गुट) ने पचास वर्षोंसे हिंसात्मक आन्दोलन चलानेके बाद १३ वर्षोंसे केन्द्रके साथ संघर्ष-विराम समझौता कर रखा है। इस सम्बन्धमें केन्द्रसे बातचीतके ६९ दौर हो चुके हैं। फरवरीके अन्तिम सप्ताहमें केन्द्रीय गृहमन्त्री और प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंहसे मुलाकातके बाद तय हुआ कि मईमें 'असली मुद्दे' पर चर्चा होगी। केन्द्रकी ओरसे वार्ताकार नगालैण्डके पूर्व मुख्य सचिव आर.एस. पाण्डेयने बातचीतके बाद कहा- 'जल्द ही नगा समस्याका सम्मानजनक हल निकल आयेगा', जो १३ वर्षोंसे नगा नेता सुन रहे हैं।

पूर्वोत्तरके सबसे पुराने और संघटित विद्रोही गुट नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ (एनएससीएन-आइसाक मुइवा) के नेता टी. मुइवा मणिपुरके उखरुल जिला स्थित अपने पैतृक गांव सोमदल जानेपर अड़े हैं और राज्यके मुख्य मन्त्री ओकराम इबोबी सिंह तथा केन्द्रीय गृहमन्त्री पी. चिदम्बरम उन्हें अपने गांव नहीं जाने दे रहे हैं। मुइवा अपने सैकड़ों समर्थकोंके साथ मणिपुरको सीमाके प्रवेशद्वार माओ गेटसे १० किलोमीटर दूर विस्वेमामें पड़ाव डाले हुए हैं, जहां डेढ़ महीनेसे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त है। नगालैण्ड, मणिपुर, असमको जोड़नेवाला राष्ट्रीय राजमार्ग ३९ को मुइवाके दीवाने नगा छात्र संघने जाम कर रखा है, जिसके चलते दैनिक उपयोगकी आवश्यक वस्तुओंकी आवाजाही बन्द है। पूरे इलाकेकी डेढ़ महीनेतक आर्थिक नाकेबन्दीके बाद छात्रोंने कर्फ्यूमें थोड़ी ढील देनेके जवाबमें दैनिक उपयोगकी जरूरी चीजोंसे लदे कुछ ट्रकोंको मणिपुर जाने दिया। मणिपुर राइफल्सने पूरे इलाकेको घेर रखा है और मुइवा समर्थक छात्र तथा आसपासके लोग कर्फ्यू तथा घेराबन्दीके बावजूद वहांसे टससे मस होनेको तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि अपने नेता मुइवाके साथ उनके गांव हर हालमें जाना है।

मईके पहले सप्ताहसे तनाव बढ़ा हुआ है, जब मुइवाको अपने गांव जानेसे रोकनेके लिए माओ गेट और उसके आसपास तैनात सुरक्षा बलके जवानोंके साथ भिड़न्तमें दो छात्र नेताओंकी मृत्यु हो गयी और एक हजारसे ज्यादा लोगोंको पड़ोसी नगालैण्डके गांवमें घुसकर जान बचानी पड़ी। केन्द्रीय गृह सचिव जी.के. पिल्लईकी ओरसे चिदम्बरमकी अपील दो-दो बार मुइवाके पास पहुंचनेके बावजूद जब कोई अन्तर नहीं पड़ा तो पिल्लई और केन्द्रकी ओरसे नियुक्त शान्ति वार्ताकार आर.एस. पाण्डेयने उसी जगह (विस्वेमा) पर नगालैण्डके मुख्य मन्त्री नेफियू रियोके साथ बैठक की, जहां मुइवाने अपना पड़ाव डाला हुआ है और फिरसे अपील दुहरायी कि मुइवा फिलहाल अपने गांव जानेका कार्यक्रम स्थगित कर दें। स्थिति सामान्य होनेके बाद इसकी व्यवस्था की जायगी।

उसके जवाबमें मुइवाके नेतृत्ववाले 'संघीय नगालिम सरकार' के प्रवक्ता और दीमापुर स्थित एनएससीएन हेडक्वार्टरके प्रमुख वी.एस. अटेमने उसी जगह संवाददाता सम्मेलनमें बताया कि उनके महासचिव 'प्रधान मन्त्री' मुइवाके यहांसे वापस लौटनेका सवाल ही नहीं उठता। अगर सरकार कायदेसे जाने देती तो मुइवा पहलेके कार्यक्रमके मुताबिक ३-१० मईतक अपने गांव रहकर लौट आते। अटेमने यह बतानेसे इनकार कर दिया कि मुइवा कर्फ्यू तोड़कर कब माओ गेट पार करेंगे और कबतक सोमदलमें रहेंगे।

प्रादेशिक परिदृश्य/पूर्वोत्तर

❑ शशिधर खान

केन्द्रीय गृहमन्त्रीने पूर्वोत्तर दौरेका कार्यक्रम बनाया, लेकिन मणिपुर नहीं गये। मिजोरमसे असम पहुंचे और वहांके मुख्य मन्त्री तरुण गोगोईको उल्फासे बातचीत करनेका पूरा अधिकार देकर अपनी एक बला टाली। असमके विद्रोही गुट यूनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट ऑफ असम (उल्फा) 'स्वतन्त्र स्वाधीन असोम' की मांगको लेकर आन्दोलन कर रहे हैं, जिसके नेता अरविन्द राजखोवाको सरकारने जेलमें डाल रखा है। मणिपुर, नगालैण्ड, असम और अरुणाचल प्रदेशके नगाबहुल इलाकोंको मिलाकर 'स्वतन्त्र सम्प्रभु नगालिम राष्ट्र' (राज्य नहीं) की मांग केन्द्रसे मनवानेके लिए एनएससीएन (मुइवा गुट) ने पचास वर्षोंसे हिंसात्मक आन्दोलन चलानेके बाद १३ वर्षोंसे केन्द्रके साथ संघर्ष-विराम समझौता कर रखा है। इस सम्बन्धमें केन्द्रसे बातचीतके ६९ दौर हो चुके हैं। फरवरीके अन्तिम सप्ताहमें केन्द्रीय गृहमन्त्री और प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंहसे मुलाकातके बाद तय हुआ कि मईमें 'असली मुद्दे' पर चर्चा होगी। केन्द्रकी ओरसे वार्ताकार नगालैण्डके पूर्व मुख्य सचिव आर.एस. पाण्डेयने बातचीतके बाद कहा- 'जल्द ही नगा समस्याका सम्मानजनक हल निकल आयेगा', जो १३ वर्षोंसे नगा नेता सुन रहे हैं। लेकिन अब मुइवाका धैर्य जवाब दे रहा है, क्योंकि हिंसासे ऊबकर उन्होंने संघर्ष- विरामका रास्ता इसलिए अपनाया ताकि बातचीतके जरिये समस्याका हल (नगालिम गठन) निकल आयेगा। केन्द्रके लिए इस समस्याका नगा नेताओंके मुताबिक हल निकालना सम्भव नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधानके अन्तर्गत इस तरहका प्रावधान नहीं है, न ही ऐसा कोई संशोधन किया जा सकता है। मगर मुइवाको अपनी मांग मनवानेसे मतलब है, चाहे भारत सरकार जैसे भी पूरा करे। इसलिए फरवरीमें बातचीतके बाद वे पहलेकी तरह विदेशी अड्डेपर लौटनेके बजाय नगालैण्डके दीमापुर स्थित अपने हेडक्वार्टर गये और अपनी तथाकथित 'संघीय नगालिम सरकार' का ३०वां गणतन्त्र दिवस समारोह मनाया। इसकी तैयारी योजनाबद्ध तरीकेसे पहले ही कर ली गयी थी, इसलिए समारोहमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय संविधान थोपनेकी केन्द्रकी कोई साजिश नहीं चलने दी जायगी और फिर वे अपने पैतृक गांव जाकर तमाम नगा संघटनोंको एकजुट करनेकी योजना कार्यान्वित करनेमें जुट गये। मुइवा अपनी सरकारके स्वयंभू प्रधान मन्त्री हैं और इनके दूसरे नेता आइसाक राष्ट्रपति हैं। मुइवाके प्रतिद्वन्द्वी खपलांगके साथ भी केन्द्र सरकारका संघर्ष-विराम समझौता ९ सालसे चल रहा है। खपलांग एनएससीएनके तथाकथित 'संघीय नगालिम सरकार' के राष्ट्रपति हैं और उनके प्रधान मन्त्री हैं किटोवी झिमोमी। खपलांगके नेतृत्ववाले गुटको बातचीतके जरिये समस्याका हल निकालनेपर भरोसा नहीं है। इन्हें भी पूर्वोत्तरके नगा आबादीवाले इलाकेको मिलाकर 'स्वतन्त्र सम्प्रभु नगालिम' चाहिए। दोनोंने हिंसाकी बदौलत अपनी मांग पूरी करनेकी लड़ाई साथ मिलकर लड़ी है। १९९० से दोनों अलग-अलग गुटोंमें बंटकर सुरक्षा बलोंको शिकस्त दे रहे हैं। इसलिए केन्द्रने दोनों गुटोंसे संघर्ष-विराम समझौता अलग-अलग किया है। लेकिन केन्द्रने बातचीतके लिए खपलांगको आजतक नहीं बुलाया। दोनों गुटोंका कहना है कि उनके पास अपनी सरकार, अपना प्रशासन सब कुछ है, लेकिन उनकी जमीन (लिम) पर भारत सरकारने कब्जा कर रखा है। खपलांग गुटने भी अपना ३० वां गणतन्त्र दिवस दीमापुरमें ही मुइवाके बाद मनाया, जिसमें 'प्रधान मन्त्री' झिमोमीने साफ कहा कि उन्हें बातचीतके जरिये कोई भी हल निकालनेपर भरोसा नहीं है। लेकिन 'सम्प्रभुता' की लड़ाई लड़नेवाले किसी भी गुटका साथ देंगे, क्योंकि नगाओंकी सम्प्रभुताको छोड़ और कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने केन्द्रको चेतावनी दी कि अलग-अलग संघर्ष-विराम करके अलग-अलग बातचीतसे 'असली मुद्दे' को लम्बे समयतक टालनेकी राजनीति नहीं चलने दी जायगी। उन्होंने याद दिला दिया कि नगा संघटनोंमें कई बार फूट पड़ी है, लेकिन आन्दोलन ठण्डा नहीं पड़ा। झिमोमीके मुताबिक उदारवादियोंको झांसा देकर केन्द्रने १९६३ में नगा पीपुल्स कन्वेंशनमें फूट डाली, जो भारतीय संविधानके अन्तर्गत नगालैण्ड राज्यके गठनपर सहमत हो गये। असम, मणिपुर, नगालैण्ड- किसी भी राज्यके मुख्य मन्त्री नगालिम गठनके लिए अपनी एक इंच जमीन छोड़नेको तैयार नहीं हैं। चूंकि सबसे ज्यादा मणिपुर और नगालैण्ड नगा आन्दोलनका गढ़ रहा है, इसलिए इन दोनों राज्योंके मुख्य मन्त्री ज्यादा परेशान हैं लेकिन साथ-साथ अपने मतलबकी राजनीति भी कर रहे हैं। १२ मईको केन्द्रीय गृह सचिवकी ओरसे आयोजित माओ गेटके पास विस्वेमा बैठकके बाद उसमें शामिल नगालैण्डके मुख्य मन्त्रीने ६ मईकी हिंसाके लिए मणिपुरके मुख्य मन्त्रीको जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि इबोबी सिंहने जानबूझकर तनाव बढ़ानेके लिए मुइवाको माओ गेटके पास जबरन रोका और कर्फ्यू लगा दिया। मिशनरी समर्थित ३० नगा संघटनोंके संयुक्त मंच हो-हो और नगा छात्र संघके नेताओंने उसी दिन प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंह और केन्द्रीय गृहमन्त्री चिदम्बरमको फैक्स भेजकर बताया कि मुइवा हेलीकॉप्टरसे अपने गांव जानेकी खानापूरी नहीं करना चाहते, वे सड़क मार्गसे ही अपने गांव जानेकी योजनापर कायम हैं। आन्दोलन यही लोग मिलकर चला रहे हैं, जिन्होंने मुइवाको एक दिन पहले चिदम्बरमका सन्देश सुनाया कि केन्द्र सरकार उन्हें हेलीकॉप्टरसे अपने गांव भेजनेको तैयार है।